

नाम - डॉ. प्रदीप कुमार राय (एसो. प्रोफेसर राजनीति शा. विभा. रोहतास मेडिकल कॉलेज, सासाराम)

विषय - राजनीतिशास्त्र
कक्षा - बी. ए. (प्रतिष्ठा) भाग - 02

पेज - 04 (भाग 02)

दिनांक - 10.07.2020

टापिड - महासभा - आधिकार और कर्तव्य (भाग-02)

विचारालम्बक कार्य - सु. परिषद् के अंतर्गत विचारणीय विषयों पर महासभा वाद-विवाद कर सकती है। किंतु जबतक परिषद् महासभा के निर्णयों को मानने के लिए तैयार नहीं रह सकती है। सु. परिषद् तथा अन्य अंग अपने वैयक्तिक कार्य विवरण की रिपोर्ट महासभा के पास भेजते हैं और सभा में इन पर विचारणीय के रूप में विचार होता है।

निर्वाचन संबंधी - महासभा द्वारा सु. परिषद् के अध्यक्षों, अधिकतया सामानिक परिषद् के सदस्यों एवं न्यास परिषद् के अध्यक्षों लक्ष्यों का निर्वाचन होता है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के लक्ष्यों को निर्वाचित करने का अधिकार समान रूप से महासभा एवं सुरक्षा परिषद् को है। सुरक्षा परिषद् ही अनुमति देने पर ही महासभा नये लक्ष्यों को पर्यवेक्षण करने की अनुमति देती है। सं. रा. संघ के सदस्यों की नियुक्ति भी महासभा सु. परिषद् की सिफारिश पर करती है।

बजट संबंधी - सं. रा. संघ का आय-व्यय महासभा द्वारा ही स्वीकृत होता है जिससे कि इसका अन्य अंगों पर स्वतः ^{आर्थिक} नियंत्रण हो जाता है।

निष्कासन संबंधी - उद्घाटन राप्टों को निकालने का अधिकार महासभा को प्राप्त है। अहीरसी पद्धति सु. परिषद् के अनुरोध पर कुछ समय के लिये संघ की सदस्यता से हटा सकती है। किंतु यदि रोड चार्जर के आरोपों और सजाओं की नतीजा अयहेलना करता है तो सु. परिषद् के अनुरोध पर ~~सदस्यता~~ के लिये महासभा उसे सदा के लिये निकाल सकती है।

ऐतिहासिक कार्य - आर्टिकल अनुसार महासभा के ऐतिहासिक और अनिवार्य के प्रकार के कार्य हैं। ऐतिहासिक कार्य के अंतर्गत शोषित स्थापना, अंतर्राष्ट्रीय शोषित के खतरे को दूर करना, सुरक्षा तथा निरस्त्रीकरण के लिये समस्त देशों में सहयोग स्थापना कीजिये करना। इन सब विषयों के संबंध में महासभा तभी अपना मत निर्धारित कर सकती है जब सु. परिषद् उसे परामर्श के लिये अनुरोध करे।

अनिवार्य कार्य - इसके अनिवार्य कार्य निम्नोक्त हैं -
(1) सं. रा. संघ का बजट पास करना (2) सु. परिषद् तथा अन्य संस्थाओं एवं संगठनों की रिपोर्टों पर विचार करना (3) न्यास परिषद् पर निर्वाचन करना (4) अंतर्राष्ट्रीय सदस्यों

के उद्देश्य से आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक शिक्षा तथा स्वास्थ्य के संबंध में
अध्ययन व जांच-पड़ताल करवाकर तत्तत्तरीय प्रयत्न करके (5) प्रत्येक
प्रकार के विना जाति, लिंग, भाषा व धर्म के मानव अधिकार तथा मौलिक स्वतंत्रता
का उपयोग करने के संबंध में में सहायता देना। इस प्रकार चार्जर (3) महासभा
को अपने आपुष्ट अधिकार प्राप्त हैं कि कोई भी अंतर्राष्ट्रीय महत्त्व का मसला
उसके सामने पेश हो सकता है।

सीमितियाँ - महासभा अपना कार्य संचालन 6 मुख्य सीमितियों द्वारा
करती है - (1) निःशास्त्रीकरण एवं अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा सीमा, (2) आर्थिक
और विज्ञान सीमा (3) सामाजिक, मानवीय एवं सांस्कृतिक सीमा (4)
विशेष राजनीतिक तथा औपनिवेशिक स्वाधीनता सीमा (5) प्रशासनिक
एवं बजट सीमा तथा (6) कानूनी सीमा।

शांति के लिये एकता प्रस्ताव - 63 नवंबर, 1950 को महासभा में
शांति के लिये एकता प्रस्ताव (संज्ञा) किया गया जो तत्कालीन समय में संघ
द्वारा सुपरिचरुद्धी कार्यवाही के बाधक स्वरूप लाया गया। इस प्रस्ताव के
फलस्वरूप महासभा को साम्राज्य कार्यवाही एवं सेना का उपयोग करने का
अधिकार मिल गया। इसके अनुसार यदि महासभा भी वैधानिक होनी हो तो
सुपरिचरुद्धी के प्रसंगों के कोर्ट पर का सं. रा. संघ के अधिकारी सदस्यों
के कोर्ट पर इस प्रकार के अधिकार की प्रार्थना किये जाने पर 24 घंटे की अंतर
ही विशेष आपात्कालीन अधिकार हो सकता है। इसका उद्देश्य कोर्ट-2
विकास, नोटों का, उसे प्रशासकीय लक्षण, राजनीतिक उदाहरण, लक्षण,
वीटो इंडेन्ट को मस म (6) है।

छोटी असेंबली - 1947 ई. में सुपरिचरुद्धी में स्थायी संसदों के
उत्तरविरोध एवं वीटो के दुरुपयोग के कारण विश्व सुरक्षा एवं शांति बनाये
रखने की दृष्टि से एक अंतर्राष्ट्रीय सीमा नामक सहायक अंग स्थापित
किया गया जिसे छोटी असेंबली कहा जाता है जो सदा अधिकारों में
बनी रहने वाली स्थायी संस्था है जो महासभा का सामान्य अधिकार
न होने की दशा में उसके अधिकार क्षेत्र में आने वाली प्रश्नों पर
विचार करती है।

निष्कर्ष - समय के साथ-साथ बड़े महत्त्व एवं प्रतिष्ठा में बृद्धि
हुई है तथा विश्व शांति, सुरक्षा, निःशास्त्रीकरण, पर्यावरण,
सहायता, तकनीकी विकास, मानव अधिकार, क्षेत्रीय विवाद, आतंकवाद
आदि जैसे विभिन्न मामलों में इसका प्रयास सहयोगी, सहायक
एवं सक्रियता पूर्ण रहा है। इसी लिये इसे विश्व का उन्मुक्त
अंतर्राष्ट्रीय महासभा है। (श्री 3)